जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 51 संख्याः 250 प्रभात कोटा, बुधवार 24 जून, 2026 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

मुख्यमंत्रियों को दबाकर राज्यसभा सीटें नहीं जीती जा सकतीं

कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के दबाव के बाद भी झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने उनके प्रत्याशी को राज्यसभा नहीं जाने दिया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जून। झारखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उम्मीदवार की राज्यसभा चुनाव में हार के बाद पूरी तरह अराजक स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज़ है। उसका मानना है कि सोरेन ने रिलायंस से संबंधित नाथवानी की जीत को योजनाबद्ध तरीके से संभव बनाया।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस घटनाक्रम ने झारखंड में इंडिया गठबंधन के भीतर दरारें पैदा कर दी हैं तथा इससे कांग्रेस अध्यक्ष की छवि और भावनाओं को भी ठेस पहुँची है, जिन्होंने हेमंत सोरेन से अपने उम्मीदवार प्रणव झा के लिए एक राज्यसभा सीट देने का अनुरोध किया था। हेमंत सोरेन ने अनिच्छा से इस पर सहमति भी दी थी।

दिलचस्प बात यह है कि इंडिया ब्लॉक के पास कुल 56 वोट थे, जिससे वह आसानी से दो राज्यसभा सीटें जीत सकता था।

- झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार है, सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस भी सरकार में शामिल है। खड़गे के दबाव में सोरेन ने अनिच्छा से बात मान ली, पर परदे के पीछे खेल कर दिया।
- सोरेन ने नाथवानी के साथ गुप्त मीटिंग की, जिसकी भनक लगने से कांग्रेस कुछ चौकन्नी अवश्य हुई, पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकी।
- झारखंड में इंडिया ब्लॉक के 56 विधायक हैं, मतलब वह दो सीटें आराम से जीत सकता था। इस लिहाज से कांग्रेस की जीत तय थी, पर हेमन्त सोरेन ने राजनैतिक चाल चली और निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी को जितवा दिया।
- इस घटनाक्रम ने इंडिया ब्लॉक में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का रूतबा घटा दिया और खड़गे व राहुल को अपमानित सा कर दिया।
- सवाल यह है कि क्या अब कांग्रेस झारखंड में सरकार से हटकर भाजपा का रास्ता साफ कर देगी या फिर अपमान को बर्दाश्त कर ''मूव ऑन'' कर जाएगी।

हेमंत सोरेन स्वयं दोनों सीटें चाहते थे और उन्होंने एक सीट कॉर्पोरेट समर्थित नाथवानी को देने का निर्णय लिया था।

लेकिन बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेमंत सोरेन पर दबाव डाला कि वे एक सीट प्रणव झा के लिए छोड़ें, जिसे उन्होंने अंततः स्वीकार कर लिया।

कांग्रेस तब सतर्क हुई, जब उसकी जानकारी में आया कि हेमंत सोरेन की नाथवानी के साथ बंद कमरे में लंबी और विस्तृत बैठक हुई थी।

मतदान के दौरान, राजद नेता तेजस्वी यादव के आश्वासन के बावजूद, आरजेडी के 4 विधायकों में से 3 ने नाथवानी को वोट दिया, जबकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रशासन प्रधानमंत्री की रिफाइनरी यात्रा की तैयारियों में जुटा

बालोतरा, 23 जून (निसं)। पचपदरा स्थित एचआरआरएल रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित एजेंसियों ने व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। रिफाइनरी परिसर के सामने बनाए गए हैलीपैड पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इस क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाने के साथ-साथ अस्थायी पुलिस चौकी भी स्थापित की गई है।

- हेलीपैड की सुरक्षा मजबूत की, अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की गई।

प्रस्तावित जनसभा स्थल पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए केन्द्र एवं राज्य स्तर की विभिन्न एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। रिफाइनरी परियोजना क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजीबोगरीब नीति है, भाजपा को कमज़ोर कर एनडीए को मजबूत करना

चर्चा है कि यह तैयारी इसलिए की जा रही है ताकि मोदी के बाद सरकार की कमान अमित शाह को ही मिले

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जून। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों में एक असामान्य पैटर्न देखने को मिला है: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के टूटे हुए समूह का विलय एक अत्यन्त कम चर्चित दल, एनसीपीआई में हो गया, जबकि भाजपा के लिए यह आसान होता कि वह बागी सांसदों को स्वयं में शामिल कर लेती। इसी तरह, शिवसेना यूबीटी के टूटे हुए गुट ने भाजपा में जाने के बजाय एकनाथ शिंदे गुट के साथ विलय का फैसला किया।

इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि भाजपा नेतृत्व ने भाजपा को मजबूत करने के बजाय, एनडीए को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। ऐसे समय, जब लोकसभा में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है।

इसका उत्तर कुछ हद तक नरेन्द्र मोदी के बाद उत्तराधिकार की योजना में छिपा है।

यह बात कहना जरूरी है कि पार्टी के भीतर या बाहर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है, और यदि वे कभी पद छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तो

- हाल ही में जिस तरह से तृणमूल के बागी सांसदों को भाजपा की बजाय एक गुमनाम सी पार्टी में शामिल कराया गया और महाराष्ट्र में भी शिवसेना के 6 बागी सांसदों को एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल कराया गया, उसे लेकर काफी चर्चा है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि इन बागियों को भाजपा में भी शामिल कराया जा सकता था और ऐसा होता तो लोकसभा में भाजपा की ताकत बढ़ती।
- लेकिन साथ ही उन राज्यों के क्षत्रपों, जैसे बंगाल में शुभेन्दु अधिकारी और महाराष्ट्र में देवेन्द्र फड़नवीस की ताकत भी बढ़ जाती, जो मोदी के उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे आगे खड़े अमित शाह के लिए चुनौती बन सकते थे।

वह उनका अपना निर्णय होगा। हालांकि भाजपा के भीतर हल्की-फुल्की चर्चा यह है कि मोदी की उम्र बढ़ रही है और वे शायद 2029 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राजनीति से सन्यास लेना चाहेंगे। संभावित उत्तराधिकारी की संख्या कई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी के करीबी, और गृह मंत्री अमित शाह इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने की स्थिति के लिए खुद को तैयार रखने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भाजपा के बजाय, एनडीए को मजबूत करने की चालों को, शाह को मोदी की स्वाभाविक पसंद के तौर पर स्थापित करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

विचार करने योग्य बात है: अगर शिवसेना यूबीटी के सांसद भाजपा में शामिल होते, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विकास जैफ की प्रतिनियुक्ति और विभागीय जांच दोनों ही ''गोलमोल''

कौशल उद्यमिता विभाग में कार्यरत विकास जैफ को एनओसी के बिना बायोफ्यूल प्राधिकरण में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने का मामला

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर 23 जून। कौशल उद्यमिता विभाग में कार्यरत सहायक निदेशक विकास जैफ की बायोफ्यूल प्राधिकरण में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति मात्र 2 दिन में ही हो गई, जबकि उनके मूल विभाग को इस बारे में कानों-कान खबर तक नहीं थी। परंतु जैसे ही यह मामला खुला तो कौशल विकास विभाग ने एन.ओ.सी. देने से मना करते हुए प्रतिनियुक्ति आदेश रद्द कर डाले। अब इस प्रकरण में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जब विकास जैफ से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि, ''उन्होंने इस प्रतिनियुक्ति के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था।'' परंतु जांच रिपोर्ट में सामने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हैरानी की बात यह है कि मात्र 2 दिन में जैफ को प्रतिनियुक्ति दे दी गई, लेकिन कौशल विकास विभाग से एनओसी नहीं मिली तो आदेश रद्द हो गए।
- विभाग के नोटिस के जवाब में जैफ ने कहा ''मैंने प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन नहीं दिया था'', जबकि जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि ''ग्रामीण विकास मंत्री ने इस नियुक्ति के आदेश दिए थे, जैफ खुद प्रतिलिपि लेकर विभाग में पहुंचे थे।''
- चौंकाने वाली बात यह है कि, जांच कमेटी ने इस गंभीर प्रकरण को यह कहते हुए समाप्त करने की सिफारिश कर डाली कि ''विकास जैफ को प्रतिनियुक्ति इस शर्त पर दी गई थी कि वे अपने विभाग से एन.ओ.सी. लाएंगे, चूंकि वे इसमें असमर्थ रहे, इसलिए प्रतिनियुक्ति के आदेश रद्द कर दिए गए हैं, अब प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।''

री-नीट परीक्षा में मोबाइल छुपाकर ले जाने वाली छात्रा की जमानत याचिका खारिज

जयपुर, 23 जून। जयपुर महानगर द्वितीय के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने री-नीट परीक्षा, 2026 के दौरान परीक्षा कक्ष में मोबाइल छिपाकर ले जाने और नकल का प्रयास करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही छात्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंदायका में री-नीट परीक्षा के दौरान वीक्षकों ने छात्रा को मोबाइल फोन के साथ रंगे हाथ पकड़ा था।

जमानत अर्जी में अधिवक्ता एमके शर्मा ने कहा कि आरोपी छात्रा नवयुवती है और उसे मामले की गंभीरता की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, उसके कब्जे से प्रश्न पत्र से जुड़ी किसी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाम परिवर्तन कई बार भारी भी पड़ सकता है, राजनैतिक दृष्टि से

शेक्सपियर ने कहा था, ''नाम में क्या रखा है'', पर बंगाल की राजनीति में नाम परिवर्तन दूरगामी प्रभाव डाल सकता है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जून। कुछ वर्ष पहले अमर्त्य सेन ने अपनी बेहद रोचक पुस्तक ''द आर्ग्युमेंटेटिव इंडियन'' लिखी थी। अब कोलकाता उस कथन को सच साबित करता दिखाई दे रहा है।

अपने पहले बजट की प्रस्तुति को लेकर उत्साह के बीच, नई-नई बनी भाजपा सरकार ने एक ऐसा बदलाव किया है, जिसने बंगाल में मानसून के आने के साथ ही एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

भाजपा सरकार ने कोलकाता के पार्क सर्कस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सड़क का नाम बदल दिया। पार्क सर्कस मुख्यतः मुस्लिम बहुल इलाका है। कोलकाता नगर निगम ने पार्क सर्कस सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदल दिया, जो एक मुख्य सड़क है।

- राज्य के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने अपने पहले बजट में एक अहम फैसला करते हुए पार्क सर्कस एरिया की जानी मानी सुहरावर्दी रोड का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया है।
- भाजपा ने दावा किया कि बंगाल के कसाई के नाम से कुख्यात संयुक्त बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन शाहिद सुहरावर्दी ने पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था और गोपाल मुखर्जी ने अनेकों हिंदुओं की जान बचाई थी, इसलिए सुहरावर्दी रोड का नाम बदल कर गोपाल मुखर्जी रोड करना एक न्यायसंगत फैसला है।
- लेकिन इस नाम परिवर्तन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, कहा जा रहा है कि इस सड़क का नाम डॉ. हसन सुहरावर्दी के नाम पर था, जो कि हुसैन सुहरावर्दी के चाचा थे और कोलकाता युनिवर्सिटी के पहले मुस्लिम वीसी थे। उन्होंने एक क्रांतिकारी हमले में बंगाल के अंग्रेज गवर्नर की जान बचाई थी, जिस पर उन्हें अंग्रेजों ने यह पद दिया था और उनके नाम पर सड़क का नामकरण किया था, जिसे कभी बदला नहीं गया था।

इस सड़क का नया नाम ''गोपाल मुखर्जी रोड'' रखा गया। गोपाल मुखर्जी को उस समय हिंदुओं का रक्षक माना गया था, जब कोलकाता में दंगे (कलकत्ता किलिंग) हुए थे। अगस्त 1946 में कोलकाता में हुई सुनियोजित हिंसा के दौरान, जब उग्र मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदुओं पर हमले किए जा रहे थे, तब उन्होंने कई लोगों को बचाने का काम किया था।

कहा जाता है कि इस संगठित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्रीय मंत्री कुरियन ने इस्तीफा दिया

नई दिल्ली, 23 जून। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंगलवार को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया।

राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,

- उनका राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया। भाजपा ने उन्हें वापस उम्मीदवार नहीं बनाया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह पर लिया गया।

65 साल के कुरियन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान के तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध हटने से भारत को भारी लाभ

भारत कच्चे तेल का विश्व में सबसे बड़ा आयातक है और इस छूट से भारत के आयात बिल में कमी आएगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जून। अमेरिका ने ईरान के तेल उद्योग को एक अप्रत्याशित राहत दी है।

एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत वॉशिंगटन ने 60 दिनों की छूट जारी की है, जिसके तहत 21 अगस्त तक ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, आपूर्ति और आयात की अनुमति मिल गई है। यह कदम तेहरान के साथ चल रही वार्ताओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक व्यापक शांति समझौता सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरीक्षणों को फिर से शुरू करना है।

दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक भारत के लिए इस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं।

हो सकता है कि इसका तुरंत मतलब यह न हो कि ईरानी कच्चा तेल लेकर टैंकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने लगें। लेकिन इससे नई दिल्ली के सामने एक ऐसी संभावना खुलती है, जिसका लाभ कई वर्षों से नई दिल्ली को नहीं मिला था- ऐसे समय में तेल के एक और बड़े स्रोत तक पहुँच, जब वैश्विक ऊर्जा बाजार भू-राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने एक अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी किया है, जो ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल्स से जुड़े लेन-देन की अनुमति देता है। इस छूट में शिपिंग, बीमा और बैंकिंग जैसी संबंधित सेवाएं भी शामिल हैं। यह अनुमति 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगी।

- अमेरिका ने ईरान को तेल उत्पादन, तेल निर्यात के लिए 60 दिन, यानि 21 अगस्त तक के लिए छूट दी है। यह कदम तेहरान के साथ चल रही वार्ता के दौरान सकारात्मक संकेत है।
- पर, इसका मतलब यह नहीं है कि तुरंत ही ईरान से तेल टैंकर भारत आने लगेंगे, लेकिन, इससे संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे।
- अमेरिका की घोषणा के बाद, कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं, इससे भारत में बढ़ती महंगाई में कुछ राहत मिल सकती है।

यह फैसला तब आया है, जब ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) को निरीक्षण की अनुमति देने और व्यापक कूटनीतिक वार्ताओं में भाग लेने पर सहमति जताई है। इस छूट को, प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटाने के बजाय विश्वास बहाली के कदम के रूप में देखा जा रहा है।

तेल बाजारों ने इस फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। अतिरिक्त आपूर्ति बाजार में आने की उम्मीद के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई।

भारत के लिए यह क्या मायने रखता है?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वह वैश्विक तेल कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

कच्चे तेल की कीमतों में हर बढ़ोतरी भारत के आयात बिल, महंगाई की दिशा, सरकारी वित्तीय गणनाओं और अंततः उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली ईंधन कीमतों को प्रभावित करती है।

पिछले चार वर्षों में देश के तेल सोर्सिंग पैटर्न में भारी बदलाव आया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, भारत रियायती रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बन गया। वर्तमान में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई से 40 प्रतिशत तक है, जिससे रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है।

साथ ही, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करने के लिए सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात सहित, खाड़ी क्षेत्र के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआईटी ने अयोध्या चढ़ावा प्रकरण पर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी

लखनऊ, 23 जून। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी। एसआईटी के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को यह रिपोर्ट सौंपी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने 13

- श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)